



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
04 / 17	अस्थायी निषेधाज्ञा	13.02.17	18.06.19

1. आशा कंवर बेवा सत्येन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खोह तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
2. अर्जुनसिंह पुत्र सत्येन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खोह तहसील सपोटरा जिला
3. करणसिंह पुत्र सत्येन्द्रसिंह जाति राजपूत करौली जरिये संरक्षिका खुद मॉ आशा कंवर बेवा सत्येन्द्रसिंह जाति राजपूत

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गिराजसिंह पुत्र नरसिंह निवासीयान खोह हाल वासी बाजणी तलाई श्री रामनगर
2. भूरसिंह पुत्र नरसिंह कॉलोनी वार्ड नं0 31 सांगानेर जयपुर राजस्थान।
3. विजेन्द्रसिंह पुत्र गिराजसिंह
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
5. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली।

—अप्रार्थीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:— श्री शेरसिंह वकील प्रार्थीगण।

श्री कमरपाल मीना वकील अप्रार्थी सं0 1,3,4

श्री तेजेन्द्र शुक्ला वकील अप्रार्थी सं0 2

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम खोह तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 112, 113, 116, 185, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 315, 316, 324, 344, 346, 348, 361, 396, 463, 539, 540, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 593, 595, 596, 755, 756, 757 कुल कित्ता 53 कुल रकबा 80 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज नरसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी खोह के नाम से चली आ रही है। नरसिंह मुझ प्रार्थी नं0 1 के सायला ससुर है यानि प्रार्थीया के ससुर गिराजसिंह अप्रार्थी सं0 1 के पिता है इसलिए उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। उक्त आराजीयात का अप्रार्थी सं0 1 ने पूर्व से ही अपना हिस्सा मौके पर 1/2 बाहमी बंटवारा करके अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात खोह बांध डूब मे आ जाने से जाने के कगार पर है। डूब मे जाने के कारण मुआवजा सरकार द्वारा खातेदार को दिया जा रहा है। हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 से अपने हिस्से की आराजी का दिनांक 02.02.2017 को बंटवारा अनुसार अपने नाम कराने के लिए कहा तो साफ इंकार हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हे जमीन नहीं दूंगा ना ही तुम्हे मुआवजे की राशि मिलेगी उसमे से भी हिस्सा नहीं दूंगा। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।


प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 6 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित न्यायालय नहीं आया इसलिए इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 2 तथा 5 के जवाब बंद

उपखण्ड अधिकारी  
(तारामती वैष्णव)  
सपोटरा जिला-करौली

किये गये। अप्रार्थी सं० 1, 3, 4 ने जरिये वकील उपस्थित न्यायालय होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में ना तो सजरा पेश किया है और ना ही कोर्ट फीस का हवाला दिया गया है। विवादित आराजीयात विवादित आराजीयात खोह बांध के डूब क्षेत्र में आ रही है जिसका मुआवजा वितरण भी किया जा चुका है तथा कुछ मुआवजा दिया जाना है। प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम खोह तहसील सपोटरा सम्बत् 2073-76 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजीयात में सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं हैं। अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। विवादित आराजीयात खोह सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से हितबद्ध खातेदारों को 80 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान लगभग आठ दस वर्ष पूर्व हो चुका है शेष भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। खोह बांध सिचाई परियोजना को अवाप्त करने की कार्यवाही लगभग 12 वर्ष पूर्व से प्रक्रियाधीन है अब परियोजना का डूब क्षेत्र के मुआवजे का फाईनल अवार्ड पारित हो चुका है अवाप्तशुदा भूमि पर आंशिक कार्य भी हो चुका है भूमि सिचाई विभाग को स्थानान्तरित हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीगण को कोई असुविधा भी नहीं हुई है ना ही कोई अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। प्रार्थीगण के तथ्यों को वाद पत्र में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

  
(तारामती वैष्णव आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी  
सपोटरा जिला करौली